SHRI ANNASAHIB SHINDE : The Central Government is agreed on the importance of the development of fisheries internally so as to make available cheap fish to the people of West Bengal and Assam and for our fish eating population in the country. Therefore, you will see that whereas in the Third Plan we had provided only Rs. 28 crores for development of fisheries, in the Fourth Plan, it has been increased almost thrice to about Rs. 84 crores.

Although development of inland fisheries is a State subject, so far as Bengal is concerned, we have taken special steps for development of the Sunderbans. The Sunderbans is a vast area. Whereas in no other State have taken up fisheries development yet, in West Bengal, we have taken it up as a Central Project; in view of the special situation obtaining in West Bengal, we have taken up the development of the Sunderbans as a Central project, and we are going to spend about Rs. 50 lakhs during the next four years for this purpose.

Some hon. Members had referred to the need for the development of the Chilka lake, so as to make available Chilka fish to the population in Orissa and Calcutta. We have only seven refrigerator vans in our country, but we have provided 4 to the Chilka fisheries, so that fish could be taken from the Chilka lake to Calcutta and West Bengal markets. We are going to have one more in the near future. My hon. friend had referred to the development of the Roychawk harbour.

SHRI SAMAR GUHA : 40 per cent of the Calcutta supply was coming from the fisheries from the 24 Parganas. But all those fisheries have been looted, and now they have turned bare. May I know what steps Government are going to take to redevelop those fisheries there ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am afraid my hon. friend had not properly listened to my observations. I do concede the point that disturbed conditions in West Bengal are coming in the way of development of fisheries. So far as Roychawk is concerned, I hope that within a month or two, the final sanction whould be received and it would be possible to take up the activities there.....

SHRI JYOTIRMOY BASU : It has been pending with the Finance Ministry for the last four months.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The hon. member has made some sugge stions about Namkhana harbour.....

SHRI JYOTIRMOY BASU : When are they going to commence work in Roychowk What they do between themselves and the Finance Ministry is an internal arrangement

MR. CHAIRMAN : No interruptions.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It would not be correct to say that there has been no increase in the production of inland fisheries in W.Bengal. During the last 10 15 years there has been an increase to the tune of almost 80-90 per cent. But if the law and order situation is better we are prepared to help by way of credit and central assistance. If West Bengal wants to enlarge its plan of fisheries, I am prepared to include that and see what can be done from the Centre to help West Bengal.

In regard to Assam, on the question of the Brahmaputra development the Assam Government must take some steps. Then the Centre will play its role in helping Assam.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the next item-Discussion regarding State hood for Delhi. Shri Kanwar Lal Gupta.

17.16 hrs.

DISCUSSION *RE* : DEMAND FOR STATEHOOD FOR DELHI

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, यह प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली के हरएक राजनैतिक दल एक स्वर से यह माँग कर रहे हैं कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाय लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि के केन्द्रीय सरकार इस को स्वीकार नहीं करती। 1952 से लेकर के आज तक दिल्ली के ढांचे में तीन बार परिवर्तन किया जा चुका है। पहले यहां पर पार्ट (सी) स्टेट को असेम्बली थी

1952 में। 1958 में उस को तोड़ कर नगर निगम बनाया। उस के बाद 1967 में मेट्रोपोलिटन कौंसिल बनाई गई और अब ए आर सी की रेकमेंडशन के बाद कोई नया ढांचा बदला जायगा। इस प्रकार से 15 साल में चार बार दिल्ली के ऊपर एक्सपरिमेंट किए जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान के लिए दिल्ली के लोग जो एक स्वर से मांग कर रहे हैं मन्त्री महोदय उसको स्वीकार कर लें और इस प्रकार एक के बाद दूसरा एक्सपरिमेंट दिल्ली के लोगों के ऊपर करना बन्द करें। दिन पर दिन दिल्ली के ढांचे के अन्दर डीटरिओरेशन आ रही है। मुझे मालूम है कि अगर कोई वकील किसी कमजोर केस की वकालात करे तो कठिनाई होती है लेकिन फिर भी वह कर सकता है, लेकिन अगर वकील को यह मालूम हो कि जज जो सामने बैठा है उसने दिमाग बना लिया है तो कितना भी केस मजबूत क्यों न हो, वह वकालात नहीं कर सकता। मेरा भी हाल उसी वकील जैसा है। मुझे मालूम है कि पंत जी का दिमाग बना हुआ है और मेरा केस मजबूत होने पर भी जो सरकार की तरफ से जवाब आना है वह भी मुझे मालूम है। सरकार कहती है कि यहां पर कोई प्रेसीडेंट ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि दो दो सरकारें नहीं चल सकती। मैं कहता हूं कि प्रेसीडेंड के पीछे आप जाते क्यों हैं? क्या कोई ऐसा प्रेसीडेंट है कि जिस देश की आबादी 50 करोड़ हो वहां एडल्ट फेंचाइज़ के ऊपर हरएक बालिग को मत देने का अधिकार एवं सुविधा हो? अमेरिका में भी एडल्ट फेंचाइज़ है लेकिन वहां पढ़ा लिखा होना जरूरी हैं। इल्लिटरैट को वहां मत देने की सुविधा नहीं है। लेकिन हमने दी है। कहीं भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है। वहां पर और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो दी गई हैं। 50 करोड़ की आबादी के देश में 5-6 करोड़ का यू० पी० और फिर तीन लाख सवा तीन लाख की आबादी का नागालैंड, उस को भी राज्य का दर्जा आप ने दिया है, मणिपुर को भी दिया है, त्रिपुरा को भी दिया है। तो यह भी कहीं प्रेसीडेंट नहीं है। जवाहर लाल जी कहा करते थे कि हमेशा प्रेसीडेंट्स की बात करना बेवकूफी की बात है। बदलते हुए जमाने में आप का अप्रोच नया होना चाहिए। आप कोई नया प्रेसीडेंट क्यों नहीं कायम करते? और अगर प्रेसीडेंट ही देखना चाहते हैं तो जो केपीटल है ओटावा उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर एसेम्बली है और केनाडा के अन्दर जो चार प्रांत हैं उनको जो अधिकार हैं वही वहां पर ओटावा को भी अधिकार हैं। तो प्रेसीडेंस का क्या देखना है, स्वयं दिल्ली के अन्दर 1952 में पं० जवाहर लाल नेहरु ने दिल्ली को असेम्बली दी थी—यह बहुत बड़ा प्रेसीडेंस है, इस लिये इस में प्रेसीडेंस की जरूरत नहीं है।

यह कहा जाता है कि वाशिंगटन और केनबरा का मुकाबला दिल्ली से नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन और कैनबरा जो बनाये गये, वह सिर्फ कैपिटल के किये बनाये गये, लेकिन दिल्ली की स्थिति दूसरी है,- उस का अपना पुराना कल्चर है, दिल्ली की आबादी ज्यादा है, दिल्ली की अपनी समस्यायें हैं, दिल्ली नार्थ-इण्डिया का सब से बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग सेन्टर है, इसलिये दिल्ली और वाशिंगटन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन की आबादी कितनी होगी—शायद एक लाख होगी, आस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है उस की आबादी कितनी होगी-शायद 8-10 लाख होगी, लेकिन दिल्ली की आबादी 45 लाख है। लोग ऐसी जगहों में रहते हैं जहां नागरिक सुविधायें नहीं हैं, जहां पीने के लिए पानी नहीं है, जहां शौचालय नहीं है, लोगों के घरों में रोशनी नहीं आती है, मकानों में पक्के फर्श तक नहीं हैं, यहां पर समस्यायें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं, यहां का ला-एण्ड आर्डर सिस्टम डिटीरियोरेट हो रहा है, हाउसिंग प्राबलम है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने स्वयं 1952 में दिल्ली को असेम्बली दी थी।

[श्री कंवरलाल गुप्त]

सभापति महोदय, अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि कैपिटल में एक सरकार होनी चाहिये, दो सरकारें नहीं होनी चाहियें। पिछले 12-13 सालों से एक ही सरकार है, बतलाइये कौन सा डवेलपमेंट दिल्ली का हुआ? क्या यही डवेलपमेंट है कि यहां पर इतनी मल्टीप्लिसिटि अथारिटीज़ है, कहीं नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी है, कहीं कैन्टूनमेंट बोर्ड है, दिल्ली कारपोरेशन है, डी० डी० ए० है, मैट्रोपोलिटन कौन्सिल है, लेफ्टीनेंट गवर्नर अलग है, इनके अलावा गवर्नमेंटआफ इण्डिया की मिनिस्ट्रीज़ हैं। अगर टीचर्स ने अपने पे-स्केल की बात करनी है, तो कारपोरेशन से शुरू करते हैं, उसके बाद मामला मैट्रोपोलिटन कौन्सिल में जायगा, लेफ्टीनेंट गवर्नर के पास जायगा, एजूकेशन मिनिस्ट्री में जायगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जायगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जायगा, होम मिनिस्ट्री में जायगा, रावण की तरह से 10 मुंह का राक्षस खड़ा कर रक्खा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिये एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकते, जो उनके साथ ज़िम्मेदारी से बात करके उनके मामले को तय करे। इसलिये, सभापति महोदय, जब तक दिल्ली को स्टेटहुड नहीं मिलेगा, तब तक यह बीमारी नहीं टल सकती।

एक बात यह कही जाती है कि अगर डिफरेंस आफ ओपीनियन हो जाय तो क्या होगा? दिल्ली असेम्बली 5 साल तक रही, सन् 1952 से 1957 तक, क्या मन्त्री महोदय एक केस भी कोट कर सकते हैं, जब डिफरेंस आफ ओपीनियन रहा हो और कोई गड़बड़ी हुई हो। एक केस भी ऐसा नहीं है और दिल्ली असेम्बली का रिकार्ड शानदार रिकार्ड रहा है—इस के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं।

मन्त्री महोदय कहते हैं कि दिल्ली में एक गवर्नमेंट होनी चाहिये। मैं पूछता क्या हूं दिल्ली में अभी एक गवर्नमेंट है? अगर आप ने ए० आर० सी० की रिकमंडेशन को मान लिया, तो क्या यहां पर एक गवर्नमेंट रहेगी। ए० आर० सी० ने क्या कहा है—उसने कहा है कि जो ट्रांस्फर्ड सब्जैक्टेंस हैं, उनका बजट पहले मैट्रोपोलिटन कौंन्सिल डिस्कस कर ले, उसके बाद पार्लियामेंट उसमें बगैर बदल किये उस को मंजूर कर ले। इसी तरह से ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट्स के कानून बनाने का काम पहले मैट्रोपोलिटन कान्सिल करे। वहां पास होने के बाद पार्लियामेंट उसमें बगैर बदल किये उसको पास कर दे। हां, रिज़र्व्ड सब्जैक्ट्स के बारे में उन्होंने पार्लियामेंट को अधिकार दिया होगा। इसी तरह से कारपोरेशन के बारे में बजट का सारा अधिकार मैट्रोपोलिटन कान्सिल को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह डायार्की क्यों होनी चाहिये। अगर ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट्स के बजट को पार्लियामेंट ने वैसे ही पास करना है, अगर ट्रांस्फर्ड सब्जैक्ट्स के लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट ने वैसे ही पास करना है तो फिर पार्लियामेंट मे किस लिये आना चाहिये। यह डायार्की सिस्टम क्यों चाहिये? आप कहते तो यह हैं कि हम यहां दो गवर्नमेंट नहीं चाहते, लेकिन अगर ए० आर० सी० की रिकमंडेशन को मान लिया गया तो यहां दो-तीन तो स्टैचूटरी बाड़ीज़ ही होंगी—इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, ट्रांस्पोर्ट बोर्ड, वाटर बोर्ड, मैट्रोपोलिटन कांसिल, पार्लियामेंट और इनके बाद जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं ये सब आथोरिटीज़ के रूप में बढ़ जायेंगी। जिस समय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बिल आया था उस समय भी यही कहा गया था कि मल्टीप्लीसिटी आफ अथारिटीज़ को कम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला, अथारिटीज़ बढ़ती गई और ए० आर० सी० की रिकमेण्डेशन को इम्पलीमेन्ट करने के बाद तो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मेरा कहना यह है कि ए० आर० सी० ने अपने माइण्ड को ठीक तरह से एप्लाई नहीं किया है, वह इसकी गहराई में नहीं गई है। जैसा मैंने कहा है उनको बजट की फाइनल पावर्स क्यों नहीं देनी चाहिये,

लेजिस्लेशन की फाइनल पावर उन को क्यों नहीं दी जानी चाहिये, पार्लियामेंट को इस में रखने की क्या जरूरत है ?

सभापति महोदय, आप इसको इस दृष्टि से भी देखिये–अगर पार्लियामेन्ट को लेजिस्लेशन की पावर दी गई तो क्या इस पार्लियामेंट के पास इतना समय है कि दिल्ली के कानूनों की तरफ ध्यान दे सके। पचास करोड़ लोगों की समस्यायें इस पार्लियामेन्ट को देखनी हैं, आज राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें बन रही है, उनकी समस्यायें आती हैं, कहीं डिस्मिसल होता है, कहीं प्रारोग होता है, देश के दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान से डिफेंस की समस्या हमारे सामने आती है और आप को सुनकर आश्चर्य होगा, मेरे पास यह लिस्ट है, दिल्ली के 12 विधेयक 1967 से लेकर आज तक गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास पड़े हुए हैं, यही कहा जाता है कि अण्डर-कन्सीट्रेशन हैं या पार्लियामेंट के पास हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास उनको पास करने की फुरसत नहीं है। मैं उन विधेयकों के नाम पढ़कर सुना देना चाहता हूं–दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक, 1967, सड़क-परिवहन नगर निगम संशोधन विधेयक, 1967, दिल्ली विद्युत प्रदाय संशोधन विधेयक, 1967, इस तरह से सब मिला कर 12 विधेयक हैं, कोई 3 साल से पड़ा है, कोई साढ़े तीन साल से पड़ा है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया और पार्लियामेंट को उनको निकालने की फुरसत नहीं है और मिल भी नही सकती क्योंकि पार्लियामेंट के अपने बिल, जहां तक मुझे याद है, 70 के करीब इस सदन के सामने पड़े हुए हैं। हम जब स्पीकर साहब से कुछ कहते हैं तो वह यह कहते हैं कि यह पार्लियामेंट है, दिल्ली असेम्बली नहीं है। तो बतलाइये, दिल्ली के लोगों की तकलीफों को कौन सुनेगा ? मैं मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि इस में कोई प्रेस्टिज की बात नहीं है, जब आप के पास समय नहीं है तो लेजिस्लेशन का अधिकार दिल्ली असेम्बली को देना चाहिए।

सभापति महोदय, अगर मेरिट्स पर जाय तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ने मणिपुर, त्रिपुरा, और हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिया है, नागालैंड का भी मान लिया है। नागालैंड की आबादी 4.33 लाख है, हिमाचल प्रदेश की 35.25 लाख है, मणिपुर की 11.20 लाख है, त्रिपुरा कि 15.13 लाख है, लेकिन दिल्ली की आबादी 42.41 लाख है इन सब से ज्यादा पापुलेशन दिल्ली की है। अब रेवेन्यू को देखिये-1969-70 में त्रिपुरा की रेवेन्यूरिसिप्ट्स 1 करोड़ 74 लाख है, हिमाचल प्रदेश की 17 करोड़ 98 लाख है, मणिपुर की 1 करोड़ 81 लाख है, लेकिन दिल्ली की रेवेन्यू रिसीप्ट्स 42.87 करोड़ है, इसके अलावा इन्कम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में दिल्ली से 60 करोड़ रुपया सालाना आता है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रान्ट, सब्सिडी या लौन मिलता है, मणिपुर को करीब 68 परसेन्ट उनके सारे बजट का जाता है, त्रिपुरा को 69 परसेन्ट जाता है, हिमाचल प्रदेश को 51 परसेन्ट जाता है, लेकिन दिल्ली को 10 परसेन्ट मिलता है। जो स्टेट अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, जिसकी फाइनेन्शियल वायाबिल्टी है, जिसके पास पैसा है, जिसकी आबादी ज्यादा है, जहां पर लिट्रेट्स की संख्या सब से ज्यादा है, उस को आप किसी न किसी बहाने फुल-फ्लेज्ड स्टेट नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि वह आप को सूट नहीं करता। यह ठीक है कि आज यहां जनसंघ की हुकूमत है, लेकिन पहले जनसंघ नहीं था, आप की पार्टी थी, इसलिये पोलिटिकल कन्सीड्रेशन बीच में नहीं आना चाहिये। मैरिट्स के हिसाब से यह चीज तय होनी चाहिए। ए०आर०सी० ने क्या रिकमेंडेशन दी है ? आपको याद होगा कि हिमाचल के बारे में स्टेट होम मिनिस्टर ने राज्य सभा में 9–8–68 को यह कहा था कि सिद्धान्त रूप में हम यह मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिलना चाहिए और जिस दिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जायेगी, हम उनको स्टेटहुड

[श्री कंवरलाल गुप्त]

दे देंगे। अब दो वर्ष के बाद आपने उनको स्टेटहुड दे दिया—मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है बल्कि खुशी है। लेकिन में यह पूछना चाहता हूं क्या हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल वाइबिलिटी पूरी हो गई इन दो सालों में? क्या उनको जितना पैसा चाहिए था वह पूरा हो गया? नहीं, पैसे की हालत वैसी ही है लेकिन चूंकि आपकी पालिटिक्स कहती है कि हिमाचल को स्टेटहुड दो इसलिए आपने उनको दे दिया। और दिल्ली में चूंकि आपको सूट नहीं करता है इसलिए आप देना नहीं चाहते हैं। तो आपका जो नापने का तराजू है, आपका जो गज या राड है वह हिमाचल के लिए अलग है, त्रिपुरा के लिए अलग है और दिल्ली के लिए अलग है।

सभापति महोदय, एस०आर०सी० ने मनीपुर और त्रिपुरा के बारे में यह रिकमेंडेशन दी थी कि उनको आसाम के साथ मिला दिया जाये और ए०आर०सी० की भी यही रिकमेंडेशन थी। लेकिन वहां तो आपने ए० आर० सी० की रिकमेंडेशन को धूल में फेंक दिया, हिमाचल को दे दिया और सबको दे दिया लेकिन जब दिल्ली की बारी आती है तो ए०आर०सी० को सामने रख देते हैं। तो यह डबुल स्टेन्डर्ड और डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली वालों के लिए ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, अभी उस दिन मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में कहा कि ए०आर०सी० रिकमेंडेशन के बाद हो सकता है कि दिल्ली कार्पोरेशन को तोड़ दिया जाये। दिल्ली कार्पोरेशन के एलेक्शन्स 7 मार्च, 1971 को होने वाले हैं। इसलिए पंतजी से मेरी मांग है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी फेयरनेस है तो दिल्ली का कार्पोरेशन रहने वाला है या नहीं, इस बात का फैसला आप एलेक्शन के पहले ही कर दीजिए। यह कहना गलत होगा कि हम बाद में फैसला करेंगे क्योंकि अगर जनसंघ पावर में आ गई तो आप उसको तोड़ देंगे और अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो रहने देंगे। इस तरह की चाल चलना में समझता हूं अनुचित होगा। आप चुनाव के पहले ही फैसला कीजिए कि आप कार्पोरेशन रखना चाहते हैं या नहीं। अन्डर ड्यूरेश अन्डर थ्रेट और धमकी के अन्दर चुनाव करायेंगे तो वह फेयर चुनाव नहीं होंगे।

सभापति महोदय, आज क्या हालत है? आज क्या अधिकार है? जो चीफ एग्जीक्यूटिव कोसिलर है वह नामिनेटेड आदमी है। वह मेट्रोपोलिटन के लिए रेस्पांसिविल नहीं हैं। वे अपने चपरासी को भी एप्वाइन्टमेन्ट नहीं कर सकते है। वे अपने चपरासी का ट्रान्सफर भी नहीं कर सकते है। सारी मेट्रोपोलिटन कौसिल जो कि एलेक्टेड है वह बजट के बारे में बात नहीं कर सकती है, बजट पास नहीं कर सकती है। उसको कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। और मल्टिप्लिसिटि आफ एथारिटीज तो इतनी है कि अगर किसी आदमी को अपना मकान बनवाना है तो उसे यह नहीं मालूम कि वह कहा जायेगा? एन०डी०एम०सी० के पास जाये, डी०डी०ए० के पास जाये, इम्प्रूयमेन्ट ट्रस्ट कार्पोरेशन में जाये, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हाउसिंग डिपार्टमेंन्ट में जाये, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास जाये या हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास जाये? पिलुर दु पोस्ट उसे चक्कर काटने पड़ते है। तो उनको ये चक्कर न काटने पड़े इसके लिए मैं आपके जरिए मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते है तो सही ताकत दीजिए। दिल्ली के लोग पोलिटिकल कान्शश हैं, उनकी भी कुछ पोलिटिकल एस्पिरेशन्स है। सिर्फ खिलौने से ही दिल्ली के लोगों की तसल्सी नहीं हो सकती है।

सभापति जी, मैं जानता हूं आप कई बार दिल्ली की बाजारों में जाते है। आप वहां पर साड़ी वाली दूकानों पर जायें तो देखेंगे कि औरत की कलई की हुई लकड़ी की तस्वीर लगी रहती है। बड़ी सुन्दर महिला की वह तस्वीर

होती है जिसके सभी कुछ नाक, कान, होंठ होते हैं लेकिन उसमें जान नहीं है। उसी तरह से यह मैट्रोपोलिटन कोंसिल भी है। वहां पर सारा पैराफर्नेलिया है लेकिन वह भी एक ऐसी महिला है जो कि लकड़ी की है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशन्स को पूरा करना चाहते है तो उनको कोई जानदार चीज दीजिए। आज दिल्ली के लोग रेड टेपिज्म और डिले के शिकार हो रहे हैं। आपने सारा पैराफर्नेलिया दिया हुआ है लेकिन ताकत कोई नहीं दी है।

आखिर मे मैं कुछ सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। मेरी मांग है कि मन्त्री महोदय पालिटिक्स को दूर रखकर और दिल्ली के लोगों की भावनाओं को सामने रखकर इस पर विचार करें। यह कोई मेरी पार्टी का सवाल नहीं है। मेरी पार्टी का रवैया तो सिर्फ तीन चार साल से ही बदला है। पहले हम असेम्बली के खिलाफ थे। मैं मानता हूँ कि यह हमारी गलती थी। लेकिन यह तो आपकी पार्टी है जो कि शुरू से ही इस बात की मांग कर रही है। यह एक नान-कांट्रोवर्शल चीज है कि वहां पर एक फुलफ्लेज्ड असेम्बली होनी चाहिए। अगर आपको यह बात महसूस होती हो कि यहां पर एम्बेसीज है, गवर्नमेंट आफिसेज है, केन्द्रीय सरकार है और उसको आप अलग ही रखना चाहते हों तो मैं कहूंगा कि कुछ थोड़ा सा हिस्सा दो तीन लाख की आबादी का अलग रखकर बाकी 40 लाख आदमियों को तो आप कम से कम पूरी असेम्बली दीजिए। अगर यह सुझाव भी आपको मंजूर न हो तो कम से कम कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया अपना प्रिविलेज रखे, अपना रिजर्वेशन रखे लेकिन बाकी चीजों के बारे में आप दिल्ली असेम्बली को लेजिस्लेशन की पावर, फाइनेंशियल बजट की पावर्स, एप्वाइन्टमेन्ट की पावर्स और दूसरी पावर्स दे सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में न्याय करेंगे। अगर वे न्याय नहीं करेंगे तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह न्याय करे। अगर यह सदन भी हमारे साथ न्याय नहीं करता है तो फिर हम दिल्ली के लोगों के पास जायेंगे और उनसे न्याय करने के लिए कहेंगे। लेकिन इसके लिए आप हमको मजबूर मत कीजिए। अगर आप त्रिपुरा और मनीपुर की भाषा ही समझते हैं, अगर आप कलकत्ता की भाषा ही समझते हैं जिसको कि हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर आप एजिटेन्स ही चाहते हैं और उसके बाद ही दिल्ली के लोगों की मांग को पूरा करना चाहते है तो दिल्ली के लोग उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। एक समय आयेगा जबकि आपको मजबूर कर दिया जायेगा कि आप दिल्ली के लोगों की मांग को पूरा करें।

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated-Anglo Indians) : Sir, I rise to oppose this motion. It is a little unfortunate that people who till fairly recently seemed to have taken an objective and if I may say so, a national view of this matter, appear today to be climbing, with great respect to my friend, Mr. Kanwar Lal Gupta, on a rather parochial and political handwagon. My friend has canvassed all kinds of analogies-Tripura, Himachal Pradesh and Manipur. In my respectful submission, these analogies are not only misplaced, but completely misconceived. Delhi is the capital of the country. It is *sui generis* and any of these analogies will be completely inapplicable.

My first and foremost objection is this. I venture to say that it is based, it is posited, on the interests of the nation. I am among those who believe that without a reasonably strong centre, a centre that has a reasonable degree of viability, this country will lose its national and political coherence. It will lose its nationhood. Already we see a certain recession of this viability at the centre. The Central Government is obviously in favour of certain measures like the Preventive Detention Act. But because it is in a difficult position, it is unable to implement them fully and if it does implement a measure like that, it does it rather haltingly and with its feet dragging.

What will happen if Delhi has its own legislature ? Immediately law and order will become a State subject. The results will not

[Shri Frank Anthony]

only be absurd but much worse than that; they will be disastrous. The Central Government will be an impotent spectator of communal riots and lawlessness encouraged by political parties. We saw gheraos and deliberate criminality affirmed and encouraged by the then West Bengal Government.

It will just be an impotent spectator of this kind of lawlessness. What little viability is there will be completely eroded. So far as the rest of the country is concerned, if communal riots take place in Delhi the Centre stands by as a helpless spectator, it will be brought not only into disrepute but into contempt throughout the country.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Have you scrapped the Bengal Assembly for good on that score ? You have not.

SHRI FRANK ANTHONY : But the Central Government is not placed in Calcutta. That is why I say Delhi is *sui generis*. With the Central Government placed in Delhi, to stand by as a helpless spectator, as I said, would be something which is utterly inconceivable.

Let us be frank in this matter. I do not want to point a finger or to impute motives. But there is the new class today---the politician and the minister. My friend says that 4 millions of people of Delhi with probably be behind them completely. I doubt it very much. I know something and some of the people in Delhi. I think, they regard this as a completely politically motivated demand. I agree that it will mean more jobs for the power hungry politicians--more ministerships, deputy ministerships and, you know, all the paraphernalia of the new political class. Then, of course, probably some officials may like it because it will mean more and better jobs for them.

But what will happen and is bound to happen ? There is bound to be an inflated budget. Who will meet that inflated budget? I do not know whether you are a permanent resident of Delhi; I am. People like you and me already overburdened will have to carry this further increased burden.

Almost every day I am doing cases against the Delhi Corporation, arguing them in the courts The Delhi corporation--I do not know, perhaps deliberately--has been given more powers than any corporation in the country. What happens ? You have a flabby, corpulent,inflated administration. But much worse than that is that it is an administration which is chronically in debt, which is chronically inefficient and, I say it with a great deal of regret, which is chronically corrupt. Merely enlarging the Delhi Corporation into a legislature is not going to eliminate any of these chronic features All that you will get is that you will get this unhappy image projected in much larger dimensions.

My hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, said that you have got a multiplicity of authorities I think, there he has got a reasonably good case. People in Delhi do not know where to go and to whom to go. Even when they know where to go and to whom to go, very often the going is completely meaningless because without the proverbial greasing of the palm nothing moves. I will quote an ironical position. In my professional capacity almost every day I am defending corrupt or allegedly corrupt employees of the Delhi Administration. In my capacity as an educationist when I want any plan approved I have to go and grease somebody's palm. Nothing moves without that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You should be prosecuted if you grease their palm.

SHRI FRANK ANTHONY : Why should I be prosecuted ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Because you are a criminal then. I will have to inform the police.

SHRI FRANK ANTHONY : You will not be able to prove it. It will not be even an extra-judicial confession. I once said it on the floor of the House. I went to the Home Minister and the then Mayor and told about it. I wanted a plan resanctioned, a plan that had already been sanctioned. It took me six months. A bride was demanded when I sent my PA. I said that I would thrash them and they said, let me try on one of them and for another six years I

would not get my plan. And my hon. friend says, why do we have to give bribe ?

What is happening in Delhi? Do you think that anything gets done or moves in Delhi Corporation without paying the meve ment price ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Where is the office of the Corporation ? Have you seen the office of the Corporation ? Do you know anything about Delhi ? You are living in Defence Colony, a posh colony, and are talking about Delhi !

SHRI FRANK ANTHONY : My hon. friend thinks that you must knock about in the backstreets of Delhi to know about Delhi. The people of the backstreets of Delhi come to me for their defence.

हमारे पास कौन भले आदमी आते हैं ? सब कारपोरेशन वाले आते हैं डिफेंड करने के लिए ।

In the final analysis, I beg of the Prime Minister not to give way in this matter. Delhi is a certain symbol. It is a symbol for the whole country. It is supposed to symbolise the composite character of the nation. It is supposed to symbolise the mosaic that is India, representing a pluralistic society, a multi-religious society, a multi-linguistic society. Delhi is supposed to symbolise that. God forbid, if some regional, parochial, obscurantist, party comes in power, Delhi will become the negation of the secular motif because, for some people, the secular motif is just a sort of hateful heresy. That is why I beg of the Prime Minister not to remotely even give into this demand because it will only mean an impetus all the divisive forces in the country.

It will also have a tremendous effect on the image of our country in the international sphere. We are trying to project an image from our country that is seeking out in this new age a new explosion, technological and scientific, and that trying to take a place amongst the progressive modern nations of the world. If suddenly some parochial party, comes in power, what image will be projected ? We will project an image of the country which is incorrigibly backward looking, a country that is incorrigibly hide bound by an obscurantist revivalism.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, आप कंवरलाल गुप्त जी को प्रोटेक्शन दीजिये, वह अकेले हैं ।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : मैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए खड़ा हुआ हूं । भगवान के नाम को याद करते हुए श्री कंवर लाल गुप्त ने अपना भाषण शुरु किया । मुझे तो इनको सुनकर बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात याद आ गई ।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में असैम्बली होनी चाहिये । इन्हीं लोगों ने 1967 के पहले कहा था कि नहीं होनी चाहिये । अब यह नीति इनकी कैसे बदल गई । यह बात बहुत अहम है कि यहां के लोगों को राजनीतिक अधिकार तो मिलना चाहिये ।

सभापति महोदय, आप जितने लोगों से चुन कर आये हैं वह एरिया दस लाख की आबादी का है । दस लाख लोगों में से आप मेम्बर पार्लियामेंट बने है । लेकिन यहां दिल्ली के सात मैम्बर पार्लियामेंट के हैं जिनको 5 लाख से कम आबादी में से एक चुना गया है—

एक माननीय सदस्य : दिल्ली की पार्लियामेंट हो गई है ।

श्री शशि भूषण : अगर यही बात है तो पहले तो आधे डिजाइन करें, उसके बाद असैम्बली की बात करें । राजनीतिक अधिकार पहले दिन से यहां दिये गये हैं । जब दिल्ली में असेम्बली थी तब जनसंघ का नामोनिशान तक नहीं था । उस वक्त कांग्रेस बरसरे इक्तदार थी । तभी असैम्बली समाप्त की गई थी । कहीं जनसंघ होता तो फिर यह कहना कि यह पोलिटिकल न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है । चूंकि हम थे इस वास्ते अन्याय किया गया है । उस वक्त उसकी जरूरत नहीं समझी गई । कारण यह है कि एक राजधानी में दूसरी राजधानी नहीं हो सकती है । यह सम्भव नहीं है । एक राष्ट्र में महाराष्ट्र का होना अजीब सा लगता है । इसी तरह एक घर में दो बहुओं को

[श्री शशि भूषण]

आप भी पसन्द नहीं करेंगे । उसके लिए तो कानून बन गया है, कोड बन गया है ।

अभी इन्होंने एक मिसाल दी । कनाडा में असैम्बली है । क्या वहां के डेमोक्रेडिट राइट्स हैं ये ज्यादा तारीफ करते हैं । लेकिन अमरीका में जहां फैडरल स्ट्रक्चर है या किसी और देश में जहां फैडरल स्ट्रक्चर है, वहां के कैपिटल में दूसरा कैपिटल नहीं होता है । आस्ट्रेलिया में नहीं है । वहां का एरिया दिल्ली से बड़ा है । वहां कैपिटल तो क्या म्यूनिसीपैलिटी तक नहीं है ।

दिल्ली में यहां जो कुछ है, उसको हम देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि वह कैसे चल रहा है । अगर यहां एन० डी० एम० सी० और डी० डी० ए० संस्थान नहीं होते तो दिल्ली में कोई तरक्की न होती । जब से दिल्ली में जनसंघ कारपोरेशन में आया है या मैट्रोपोलिटन काउंसिल में आया है, भारत सरकार ने इतना पैसा दिया है कि दिल्ली के पूरे इतिहास में पहले इतना नहीं दिया गया, इस पीरियड में इतना दिया गया है जितना इतने ही पीरियड में पहले कभी नहीं दिया गया । डी डी ए और एन डी एम सी ने तो सम्भाल लिया, वर्ना इनके हाथ में वह होता तो पता नहीं क्या होता ।

जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, हो सकता है कि श्री एन्थनी कभी कार्पोरेशन में न गये हों, लेकिन मैं उस बाजार में जाता हूं, जहां मेरे दोस्त पले हैं और बड़े हुए हैं । आढ़तियों की मार्केट में इतनी ब्लैक-मार्केट है कि मैं कह नहीं सकता हूं ।

पिछले दिनों क्या हुआ ? एक साल में सेल्ज टैक्स लगभग आठ गुना बढ़ा दिया । फिर जब पार्टी फंड में रुपया मिल गया, तो उसको पहले के बराबर घटा दिया । सिनेमाघर के लाइसेन्स इस तरह दिये जाते हैं कि उसके बारे में बहुत शिकायतें आती हैं । सी० बी० आई० हैरान और परेशान है कि वह कितने केसिज़ की एनक्वायरी करे ?

श्री स० मो बनर्जी : जबसे यहां जनसंघ आया है, तब से यहां जांडिस शुरू हो गया है । जांडिस का रंग भी पीला और जनसंघ का रंग भी पीला ।

श्री शशि भूषण : श्री नन्दा ने एक प्लान रखा था कि कोई ट्र-टायर सिस्टम होना चाहिए, पांच छः छोटी-छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हों, एक कार्पोरेशन हो और उन संस्थाओं का सिविक नेचर होना चाहिये । तभी दिल्ली में कोई एडमिनिस्ट्रेशन सही तौर पर और कायदे से चल सकती है । आज हालत यह है कि सारे देश से पैसा इकट्ठा कर के दिल्ली में लगाते हैं और उस का पता नहीं चलता है ।

इस वक्त भी दिल्ली की सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर है । अब भी दिल्ली के डेवेलपमेन्ट का सारा हैडेक पार्लियामेन्ट पर है । यहां पर सबसे बड़ी आबादी क्लाकर्स की है । उनके लिए मकान बनाना और दूसरी व्यवस्था करना सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का काम है । दिल्ली का जितना काम है, वह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है । सारे देश से जो बड़े बड़े अफसर आते हैं, यहां पर बिदेशों के जो दफतर हैं, वे सब सैंट्रल गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं । अगर बीच में यह नई दुकान खड़ी हो जाये, तो ऐसा लगेगा कि एक अच्छी मार्केट में एक खोखा खड़ा हो गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : और वह भी अनस्थाराइज्ड ।

श्री शशि भूषण : माननीय सदस्य ने कहा है कि मेट्रोपालिटन कौंसिल एक विषकन्या की तरह है - वह औरत की एक सुन्दर मूर्ति की तरह है, जिसमें जान नहीं है । यह ठीक है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उसमें लोग ही

ऐसे बैठे हैं, वर्ना उसके पास काफी अधिकार हैं।

इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि दिल्ली में एसेम्बली तो दूर रही, मेट्रोपालिटन कौंसिल भी न हो, सिर्फ कार्पोरेशन हो। यहां पर बेचारे शिक्षकों का बेड़ा गर्क हो गया है। उनमें दो साथी भूख-हड़ताल कर रहे हैं, जेलों में धीरे-धीरे मर रहे हैं, क्योंकि उनको कारपोरेशन, मेट्रोपालिटन कौंसिल वगैरह दुनियां भर के चक्करों में फंसा रखा है। यहां कार्पोरेशन रहे और उसका सिविक नेचर हो। तभी दिल्ली का काम अच्छी तरह चलेगा। बड़े पन्तजी ने इन्हीं सब बातों को सोच समझकर दिल्ली ऐसम्बली को तोड़ दिया था, हालांकि उसमें हमारा बहुमत था।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): It was very interesting to find the Jana Sangh Member pleading very vehemently that we should go on adding to our already multi-fold States in our country. It is all the more interesting that I, for one, who has always pleaded for more autonomy and and decentralisation, should speak against that of motion Mr. Gupta and vehe mently oppose it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: There you are allied. We know.

SHRI S. KANDAPPAN : Mr. Gupta even went to the extent of issuing a threat before he concluded his speech that there will be an agitation if the Government does not concede their demand.

I have been very carefully listening to Mr. Gupta's agruments and all the arguments that he has made in justification for creation of a separate State for Delhi, probably he would not have made if the Jana Sangh had an experience of running a State Government, because the socalled delay that he has mentioned in the administration is a day-to-day experience of all the State Governments in this country. Even the well recognised States and bigger States in this country do have that kind of difficulties while dealing with the Centre and in sending the papers. Because of the proliferation and duplication in the administration there is so much delay. Something could be done to avoid all that. But that does not justify the creation of a separate State.

The other plea was that the local aspirations; particularly, of the neglected and the down-trodden sections of the Delhi population should be met. That, I am sure, could be met by the Centre as well as by the Metroplliton Council and other agencies without the creations of a State.

Apart from what Mr. Frank Anthony has pointed out,-which is very valid argument, I would like to point out certain other factors. Mr. Gupta as well as others have got to recognise that simply because Delhi happens to be the capital of this country is has added many advantages to the residents of Delhi. Nobody can deny that. If you take the *per capita* income of Delhi it is three times of the all India average. This is to be judged by the yardstick that is allowed in juding backward or under-developed country. I think it is 100 dollars or so. That is taken as a standard. If a country has below 100 dollars that is considered to be an under-developed country and if it is above 100 dollars *per capita* that is considered to be an advanced or developed country. According to that standard I think, Delhi is a doveloped area.

How has this development in Delhi come about ? It is not as though people in Delhi were more enterprising than people elsewhere or they had more riches to plough into the developmental programmes of Delhi. Sir, it is because of the historical accident that Delhi happens to be the capital of our country. We have no grudge against it When such is the position, my hon. friend Mr. Gnpta and others have got to recognise this fact, namely, how best we are going to keep up the cosmopolitan character of Delhi. That is most vital. Sir, I think it is more important than anything else that we should give an identity to our country-men who come from various areas to Delhi, that they should feel that they are part and parcel of this great country. They should feel that it is their soil, they are part and parcel of Delhi and that they are not aliens when they live in Delhi. Unfortunately, Sir, that kind of atmosphere is lacking.

[Shri S. Kandappan]

In fact, if at all there is to be any demand for any change in the Delhi set-up, the demand should be such that the Centre should see to it that they create conditions for the continuance of the cosmopolitan character of this city which is in keeping with the polyglot nature of our country. I am afraid even the Central Government is not able to resist the impact of the Jan Sangh which is very much evidenced in the roadsides and elsewhere on the occasion of the Hindi agitation Even people like me who live in Delhi for 8 or 9 years, find it difficult sometimes to communicate with the civil authorities. We receive communications in Hindi from the Metropolitan Council or from the Municipal agencies about our Electricity or other Bills. Some times when I ring up the official concerned about my electricity bill or other bills, it is very difficult to converse with them intelligibly. They refuse to talk to us even in English. I don't know what great sin we have committed. If even Members of Parliament are being treated like this, in the capital City of Delhi, I am afraid, the country can never survive as one nation. This should be a warning for the Jan Sangh; they should be ery careful in their approach to civil problem. If they do not realise, this, then it is for the Centre to see how far they can give that kind of picture to the area and not in the way suggested by these people. Otherwise I am affraid, it protends geat danger and it will have far-reaching consequences if the Centre were even remotely to concede to that sort of demand.

I would appeal to the Government and also to the Jan Sangh Members that they have got to realise this fact and they have got to live with this fact. It is better if the Jan Sangh, with their effort and the mass following it has in Delhi area, could create conditions for the cosmopolitan character of the capital city of Delhi. And if they do this, I am sure, even people like me, would think of admiring Jan Sangh. Thank you.

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) सभापति महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी बराबर से इस सिद्धांत को मानती रही है कि राज्य का दर्जा सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, बहुत से देश के हिस्सों को दिया जाना चाहिए । आप जानते हैं कि जब जब भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने की बात आई, कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आन्दोलन में आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया । जब 1952 से 1956 तक दिल्ली के अन्दर विधान सभा थी और उसे सी क्लास स्टेट का दर्जा हासिल था उस समय भी हमने इस का समर्थन किया था । लेकिन उन दिनों जनसंघ के लोगों ने उसका विरोध किया विरोध ही नहीं किया बराबर यह प्रचार किया कि यह व्हाइट एलीफेंट है, सफेद हाथी का दर्जा इसे दिया गया है । इतना ही नहीं, भाषा-वार राज्यों का विरोध उन्होंने बराबर हर जगह किया । लेकिन अभी जब 1967 में आम चुनाव के बाद दिल्ली की बागडोर जनसंघ के हाथ में आई तब से इन के दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूर आया । संभवतः यह ऐसा समझते रहे होंगे कि इन के हाथ में कभी भी कहीं की शासन-व्यवस्था आने वाली नहीं है । लेकिन बाद को जब इन के हाथ में व्यवस्था आ गई तो यहां से वह बदले । अभी हमारे भाई गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने गलती की । तो जब आप ने इतनी भारी गलती की कि आप सही मांग का इतने दिन तक विरोध करते रहे तो आप को बहुत बड़ा प्रायश्चित करना होगा । पहले प्रायश्चित कीजिए तब इस झंडे को अपने हाथ में लीजिए वरना यह स्टेटहुड का झंडा भी आप के हाथ में जा कर बदनाम हो रहा है । इसलिए आप प्रायश्चित कर के आएं, तब इस तरह की बात करें । लेकिन मैं समझता हूं कि यह दिल से दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाना नहीं चाहते । यह स्टंट मात्र है । केवल जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ऐसा कर रहे हैं । क्यों ? क्यों कि यह समझते हैं कि पिछले चार वर्षों में दिल्ली की हुकूमत जो इनके हाथ में है, मेट्रोपालिटन कौंसिल की और कारपोरेशन की इस में इन्होंने जनता पर टैक्स बढ़ाया, इन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों को उजड़वाया, इन्होंने शिक्षकों के ऊपर हमले किए, इन्होंने ट्रांसपोर्ट की हालत खराब की, गन्दगी बढ़ाई,

प्राइवेट बसेस को, प्राइवेट आपरेटर्स को लाइसेंस दिए और केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए जो भी पैसे दिए उस का इन्होंने दुरुपयोग किया। भ्रष्टाचार इन के यहां पूरा का पूरा है। इन बातों को छिपाने के लिए यह ऐसा कर रहे है। जनता इन की बातों को याद रखेगी। मैं ने पहले ही कह दिया कि मैं समर्थन कर के बोल रहा हूं। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि अपने इन पापों पर परदा डालने के लिए, और जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए यह स्टेट के दर्जे की मांग कर रह है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अरे, आप की क्या राय है यह बताइए न।

श्री रामावतार शास्त्री : वह तो मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिलवाना चाहते हैं तो आप पीछे चले जाइए हम लोगों को आगे रहने दीजिए जो सही माने में लड़ने वाले हैं। आप तो सही माने में लड़ने वाले नहीं हैं। आप तो जनता को धोखा देना चाहते हैं। इसीलिए इस बात को छिपाने के लिए यह आप कर रहे हैं।

आखीर में, मैं यह कहना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार से और पंत जी से कि आप केवल राज्य के दर्जे का विरोध करते रहेंगे तो उस से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के विकास के लिए क्यों कि हमारे सरकारी कर्मचारी रहते है, मजदूर रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं हैं, अच्छी ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था नहीं है, इन तमाम व्यवस्थाओं में योगदान दीजिए ताकि जनता इन के बहकावे में जाय। यह जो उलटी बात कह रहे हैं वह उस न में न आए। यहां का विकास हो और जनता सचमुच में समझे कि जनता के आन्दोलन के बल पर ही दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है और इन्होंने जितने पाप अब तक किए हैं कारपोरेशन के जरिए या मेट्रोपोलिटन कौंसिल के जरिए, उन पापों की जांच होनी चाहिए। इन्होंने पैसा ठीक से खर्च किया या नहीं किया, इंतजाम ठीक से किया या नहीं या इन्होंने भाई भतीजावाद किया, गोलमाल किया, कितना पैसा खा गए इसकी सब की जांच होनी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : जांच तो मार्च के एलेक्शन में होगी। आप अपने कैंडीडेट तो खड़े करिए।

श्री रामावतार शास्त्री : वह तो हम करेंगे उसी से बचने के लिए तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि स्टेटहुड आप से नहीं आएगी। दिल्ली की जनता लड़ कर के स्टेटहुड दिल्ली के लिए लेगी। आप के जांडिस के झटे के मातहत दिल्ली को स्टेटहुड नही मिलेगा। जनता अपना आन्दोलन कर के, लड़ कर के दिल्ली का स्टेटहुड हासिल करेगी।

श्री रणधीर सिंह : (रोहतक) : सभापति महोदय, मेरे पास आज की डिबेट है। इस का एक बहुत अच्छा फारमूला तैयार है जिस में गवर्नमेंट की बात भी रह जाये और जिस चीज के लिए बेताब हैं मेरे भाई गुप्ता जी, इन की फुल स्टेट की बात भी पूरी हो जाय। वह यह है दिल्ली जो एक बच्चा है वह उस को दिया जाय जो उस के सही वालिद हैं, जो सही वालिदैन हैं। वैसे तो सारे हिन्दुस्तान का हिस्सा है लेकिन तवारीख देखी जाय, आप तो जानते हैं महाभारत के वक्त से लेकर 1911 तक दिल्ली हरयाना का हिस्सा रही है। महाभारत के वक्त से जब कि हस्तिनापुर इसकी जगह थी और कुरुक्षेत्र में जाकर लड़ाई हुई उस वक्त से लेकर 1911 के वक्त तक दिल्ली हरयाने का हिस्सा थी। रोहतक तहसील थी और दिल्ली जिला था, आप ताज्जुब करेंगे। यह कोई हवाई बात नहीं मैं करता, तवारीखी बात है। यह ज्योग्राफिए की बात है। तो मैं तो यह कहूंगा

[श्री रणधीर सिंह]

कि यह झगड़े की बात और जनसंघ की बात, यह उटपटांग बातें तो जाने दीजिए और सीधी बात लीजिए। जमीन किस की? जो बोवे उसकी। और दिल्ली उसकी जिसकी पहले थी। क्योंकि हम बहादुर आदमी थे उस इलाके के, अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े थे सन 1957 के गदर में लिहाजा हमारे उन्होंने चार हिस्से कर दिये। कुछ हिस्सा यू. पी. में मिला दिया, कुछ राजस्थान में मिला दिया, कुछ हिस्सा दिल्ली को छोड़ दिया और बाकी हिस्सा पंजाब को दे दिया। अब एक हिस्सा पंजाब से कट कर हरियाना बना। तीन हिस्से अभी और बाकी हैं। दिल्ली को मिला दीजिये, वेस्टर्न यू. पी. के कुछ हिस्से हैं जो हमारे थे वह हमें दे दीजिए और राजस्थान के वह हिस्से हमें दे दीजिए। पूरा हो जायेगा और मैं गुप्ता जी से कहूंगा वह भी इस बात को उठाएं। इस बात में बड़ा वजन है। मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि वह इस को माने। सीधी बात कहनी चाहिए। यह हम नहीं चाहते कि दिल्ली में लट्ठमलट्ठ हो जाये, यह नहीं है कि इसकी इन्टरनेशनल पोजीशन खत्म हो जाये। आप एक हदबन्दी कर दीजिए जैसे नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का एरिया है, उसके साथ और भी लेना चाहें तो वह भी ले लें लेकिन बाकी दिल्ली उसमें मिला दें। आखिर दिल्ली ने कौनसा कुसूर किया है? इसलिए पुरानी दिल्ली के साथ जितना इलाका है देहात का और पुरानी दिल्ली का वह मिला कर हमें दे दें। यह मैं नहीं कहता, यह गांधीजी ने कहा था, आसफ अली ने कहा था, देशबन्धु गुप्ता की यह मांग थी और कांग्रेस का यह रेजोल्यूशन था और जो रिपोर्ट बनी है स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन कमेटी की उसमें भी यह बात थी कि हमारे जितने रिश्ते नाते हैं, जो शादी व्याह होते हैं वह दिल्ली में होते हैं या यू० पी० में होते हैं। हमारा मोड आफ थिंकिंग, वे आफ लाइफ, मोड आफ लिविंग सब एक ही है। तो आजकल चूंकि ज्यादा अूशियन हालत गुजर रही है इसलिए वह बात तो मै नहीं उठाता हूं। लेकिन यह बात मैं जरूर कहता हूं कि इनकी जो मांग है वह तभी पूरी होगी, फुल स्टेट हुड की कि हरयाना फुल स्टेट है उसके साथ शामिल हो जाइये आप, आप की फुल स्टेट बन जायेगी। और इस एरिया मे आगे जो आने वाला कैपीटल है उसके लिए पूरा एरिया न्यू डेली का और मिलाकर लें लीजिए। मैं समझता हूं कि आप इस बात को सोचगे और गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान देगी। और आखिर में यही बात बनेगी। और कोई इसका इलाज नहीं है। वरना यह अपनी डेढ़ ईंट की खिचड़ी हमेशा अलग पकाते रहेंगे और हमें तंग करते रहेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर): सभापति जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो बहस हुई है उस पर एक वाक्य कहूंगा कि अगर भ्रष्टाचार है, साम्प्रदा वाद हैं, शिक्षकों की तनख्वाह नहीं मिलती तो यह केवल दिल्ली में ही नहीं हैं, सारे हिन्दुस्तान में है। फिर दिल्ली पर ही क्यों यहां की सरकार हुकुमत करे? असल में यह आप अगर इतिहास का तथ्य देखें तो कभी भी इस दिल्ली का मालिक दिल्ली वाला नहीं बना है। कभी कोई खैबर दर्रे से आया, कोई अरब सागर से आया लेकिन इधर बीच में कुछ लोग इलाहबाद की तरफ से चले आये हैं। नतीजा यह हुआ कि बार बार बाहर से लोग यहां आकर मालिक बनते रहे और बेचारे दिल्ली वाले चुपचाप देखते रहे लोगों का जाना और आना। इसलिये यदि आप हिन्दुस्तान का इतिहास देखें तो आपको मालूम होगा कि जितनी बार यह देश गुलाम हुआ, उतनी ही बार दिल्ली गुलाम हुई, दुनियां के किसी भी देश की दिल्ली उतनी बार गुलाभी नहीं हुई होगी।

इसलिए, सभापति महोदय अगर दिल्ली की जनता को ताकत देनी है, दूसरी जगह के लोग जो यहां का बिज होने के लिए आये उनका मुकाबला करने के लिए तो दिल्ली की जनता को जम्हूरियत का हक देना होगा। यह बात मैं सिर्फ कंवरलाल जी की वजह से नहीं कह

रहा हूं, जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्होंने भी दिल्ली को हिन्दुस्तान से अलग कर दिया। मैं पंतजी या इनकी प्रधान मन्त्री की बात नहीं कह रहा हूं, इनके पुरखे लोग जब यहां मालिक थे, पं० जवाहरलाल नेहरु, पं० गोविन्द बल्लभ पंत भी यही कहा करते थे कि दिल्ली तो सारे हिन्दुस्तान की है, केवल किसी एक जगह की नहीं बनेगी, नहीं तो बहुत सी बीमारियां फैलेंगी, खास तौर से जो मुकामी बीमारियां फैलती हैं। यही बुद्धि जो देश के एक हिस्से को सारे हिन्दुस्तान का कहती है, वही बुद्धि जब हिमाचल की सरहद पर चीन का कब्जा होता है, उस समय कहती है कि यह जमीन कंकरीली है, पथरीली है। क्या दिल्ली ही सारे हिन्दुस्तान का है, मद्रास नहीं है, बम्बई नहीं है। इस तरह से देश को तोड़ने का तरीका कब तक चलेगा।

मैंने सुना है कि सारी दुनियां के लोग यहां आयेंगे उनको दिखलाने के लिए दिल्ली को खूबसूरत बनाना है। यह सही है कि अभी कनाट प्लेस में 27 लाख रुपये का फव्वारा लगा कर कुछ परदेसियों को चहकाने के लिए, उनकी आंखों को तरावट पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है, बहुत बढ़िया चीज बनाई गई है, लेकिन यह भी सही है कि उसी फव्वारे की बगल में आज जाड़े के दिनों में फटी हुई बनियान पहने कई लड़के चार आने का चना बेचते घूमते फिरते हैं, कैसे दिल्ली को सुधारेंगे? दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से को सुधारने के लिये, उसको साफ बनाने के लिए जरूरी है कि आप देश में दौलत पैदा करें, लेकिन वह तो आप करने वाले नहीं हैं। एक तरफ नई दिल्ली में फव्वारा और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलते हैं। क्या आप समझते हैं कि रूसी दूतावास वाले या फ्रान्सीसी दूतावास वाले पुरानी दिल्ली के रिक्शा नहीं देखा करते।

जब एटंनी साहब ने इसका विरोध किया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये जनता के बीच के आदमी नहीं हैं, आपने इनको नियुक्त किया है, इसलिये वे अपनी नियुक्ति की फीस दे रहे थे आपका समर्थन कर के। लेकिन चौधरी रणधीर सिंह और दूसरे लोग जो जनता के बीच में रहते हैं वे जब विरोध करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। यह कंवर लालजी की मांग है या शास्त्री जी की मांग है या मेरी मांग है, इस बात को छोड़ दीजिये, मैं तो पंतजी से यह कहूंगा कि इस सवाल पर ही आप एक बार दिल्ली में वोट करा लीजिये। दिल्ली के लोग दिल्ली के लिये पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं या नहीं इस पर वोट हो जाये और वे पूर्ण राज्य के पक्ष में नहीं हैं तो मत दीजिये, लेकिन अगर दिल्ली की जनता मांगती है तो जरूर दीजिये मैं बार-बार आप से यही मांग करता हूं।

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam): I am standing here to support the demand of Statehood for Delhi. In supporting this demand we are only continuing to follow our party's policy which has been there for the last decade. Wherever there have been aspirations of the people to form a separate State, the Communist party has always supported them. Even when the Jana Sangh and other people were opposing the formation of linguistic States, we supported Statehood for those areas.

The political aspirations of the people of Delhi must be considered and we must not think about the party ruling here. We must not be afriad of the Jana Sangh people who are now ruling this Metropolitan Council.

Your argument against granting of Statehood to Delhi is that the Metropolitan Council here is corrupt and that if Statehood is given to Delhi, corruption will go on. I do not agree that this Metropolitan Council alone is corrupt. Can you say that the State Governments and even the Central Government are not corrupt? They are all corrupt. Corruption and nepotism are there in the Central Governmet also. So, why do you bring that charge for not granting Statehood to Delhi?

We have to consider the political aspi-

[Shri K. M. Abraham]

rations of the people and we are going to support the wishes of the Delhi people and their cause.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISIRY OF HOME AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K C PANT) : We have had an interesting debate and I think Shri Kanwar Lal Gupta will have seen from the general trend of the debate that those who have approached the problem objectively have laid emphasis on the composite character of Delhi and on the need to keep Delhi as the capital of the whole country, something which belongs to the whole country and those who have taken a political approach, while they were apologetic in supporting his party have nevertheless lent their political support. This is the sum and substance of the debate that has taken place. Mr. Misra refered to the fact that Delhi grew over the ages with people coming in from Central Asia and other parts. I think he has a point there, Delhi has grown over the ages and Delhi has been a kind of crucible into which various nationalities and religions and streams of culture in our own country have melted to form what can be called a composite culture which reflects the composite culture of our own country. In that sense he is right. If you go into the figures of the last sixty years or so, in 1911 the population of Delhi was a little over two lakhs; today it is 42 lakhs Where have these people come from ? They have not grown out of the soil of Delhi. They have come from all over the various provinces made Delhi; and Delhi has been built up with the influx of people from all over the country. This is what Delhi is today; this is what it should be; this is at it should remain.

Shri Kanwar Lal Gupta : spoke of the grand alliance on this occasion. Knowing the fate of the earlier grand alliance he was a very courageous man, though not a very wise one. He says there was politics in this. There is no question of politics. He himself referred to the fact that four different experiments hove been carried out in the last fifteen years. These experiments were carried out during the period in which the Congress was in power both at the Centre and also in Delhi. All those experiments were carried out during that period He himself says that at that time when his party was opposing the statehood on the ground that we should have a strong centre, the Congressmen were wanting a separate State for Delhi. Now, is it taking a political view if the Central Government, which happened to be also that of the Congressmen, took the view that in the larger interest they should not give in to the pressures of their own partymen at the local level because the larger interests dictated otherwise? Is that a political view or is that a national view ? That is the view that Congressman took at that time in the Centre. He has had a taste of power in a very small part of the country for a small period of time; let him not build too much upon that. He should not say that just because the Jan Sangh is today in power for a few years in Delhi we who are sitting here with all the experience of so many years are going to let that factor weigh at all in our mind while taking a decision on Delhi. He should see this thing in its proper perspective.

My hon. friend Shri Randhir Singh put forward a theory that the real parent of Delhi was Haryana.

Sir, the real parents always realise that after a certain age the child will be independent. (*Interruption*) An Hon. Member : Very nice.

SHRI K. C. PANT : So, I think that he would not like to tie Delhi to the apron-strings of the old parents.

श्री कंवर लाल गुप्त : इनको जमुना पर लेजाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है।

SHRI K. C. PANT : My hon. friend referred to Nagaland, Manipur, Tripura and Himachal Pradesh. Shri Anthony has answered that point briefly and succinctlyand effectively,and he has said that that is not proper analogy, because Delhi is the capital of the country and that makes the whole difference You must realise that these are areas which require special treatment; they are areas which require special considera tion for development. Certain experiments

were tried out therefore over a period of time, over the last 15 to 20 years; they have developed and have reached a certain stage of development and they have become States. That is, altogether a different process which was required to develop those backward areas. But Delhi's case as the capital of the country is not on all fours with them and has to be considered differently.

Sir, if we look at the problem of Delhi, we must look at it from the point of view of the needs of the capital and on its own merits. We must not mix it up with the other issues here. It was said earliar by Shri Kanwar Lal Gupta that the various political parties had gone into this matter and raised certain demands. He had even threatened agitation towards the end of his speech. I would like to tell him that this is a matter which should be considered coolly and considered dispassionately, because it is something which is of interest not only to the people of Delhi, but it is something which is of interest to the people of the whole country. And when he talks of representive Government, does he realise that it is only Delhi which has the unique distinction of being ruled directly by that Government that is representative of not a few lakhs, not 40 lakhs, but of 50 crores ? It is not an unrepresentative Government that sits here.

Going back, I would like him to apply his mind coolly to the problem. After all, Delhi became the capital in 1912, and till then Calcutta was the capital. If you try to understand the reasons for shifting the capital from Calcutta to Delhi, even at that time, the Secretary of State for India had said that the arrangement-as he frankly described it-is a bad one for both. He has given reasons why, and the reasons are simply that the Central Government has certain responsibilities in the Centre. It must be able to discharge those responsibilities.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : That is the British way of thinking.

SHRI K. C PANT : So, this is the problem. Why do you try to confuse the issues ? This is the problem that remained-two Governments in one place having simultaneous jurisdiction over a certain area. But leave aside the opinion of the British. I agree with him that they were not part of this country; let us reject their view.

Let us take the view of our own experts. Let us take the view of the SRC. I hope Shri Kanwar Lal Gupta will not acuse them of being foreigners.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The SRC has quoted the Secretary of State.

SHRI K. C PANT : So, the SRC is now suspect because it has quoted the Secretary of State : (*interruption*). The SRC has reviewed this position and recommended the merger of most of the then Part C States in the adjoining States. Because Delhi is the federal capital, the Commission wanted that it should continue to be Centrally-administred; and the Commission referred to the cirumcstances leading to a separate administrative unit being carved out for housing the capital of the country, and came to the conclusion that the scheme of division of power as envisaged in the Constitution between the Centre and the States being extended to a unit functioning in the seats of the national government would give rise to embarrassing situations. The administrative necessi y and the desirability of avoiding conflicting jurisdiction and also the practice in other countries were cited as reasons justifying direct administration of Delhi by the Central Government.

श्री कंवरलाल गुप्त : त्रिपुरा और मनीपुर के लिए एस. आर सी. ने कहा था कि इनके लिए असेम्बली नहीं होनी चाहिए लेकिन वहां पर आपने दे दिया तो आप यह डबुल स्टेंडर्ड क्यों रख रहे हैं ?

SHRI K. C. PANT : Because they are not the capital of the country. I will quote from para 589 of the SRC report:

> "If it is conceded that the national capital has to be under the effective control of the national government and both New Delhi and Old Delhi have to be treated as a single unit for administrative purposes, there will be little scope for difference of opinion on its future administrative pattern."

[Shri K. C. Pant]

These are the two basic considerations and I think any reasonable man would concede these two points.

Mr. Kanwar Lal Gupta referred to the example of the USA and Australia. But without assigning any reason, he brushed aside these two examples. They are examples of federal capitals and we have to draw a lesson from that. He suggested that a part of the territory of Delhi may be kept for central administration and the rest may be given Statehood. I would again quote from the SRC report which has dealt with this particular point:

> "The total population of the two areas, old Delhi and New Delhi taken together, at that time was only 2,32,837, according to the 1911 census. Since then, the two parts of the city have rapidly doveloped and Delhi is now an integrated and vast metropolis with an urban population of nearly a million and a half"……

that was according to the 1951 census. Today is about 42 lakhs.

> "From the point of view of Law and order, the social life of the people, trade and commerce and common utility services, old Delhi and New Delhi now constitute one integrated unit and it will be wholly unrealistic to draw a line between the two."

Today the population is 42 lakhs, but the city is still expanding fast. By 1986 its population may well be over 80 lakhs. Therefore, it is not only a question of providing for the city today but for its future expansion also. You cannot therefore, have a very insufficient area allocated for Delhi. It has to have elbow-room to expand. It is expanding as an urban centre, with a complexity of urban life. It would be wrong and impractical to carve out a portion of this organic city. It is an organic whole and we should treat it as such.

Mr. Kanwar Lal Gupta, while referring to the fact that we wanted Delhi as the capital not be given Statehood, said, there is Bombay, there is Calcutta; why don't you treat them alike ? That argument can be used the other way also. When you talk of economic viability and population Calcutta and Bombay have got a large population and also economic viability but you do not make them into States They are part of much larger States. Therefore, these considerations are not strictly relevant to the issue. The issue is, Delhi has to serve as the capital. It is an urban centre. It has certainly a certain amount of wealth. Because it is the capital, it has attracted more wealth, more industry, etc. and it has become a trading centre. It has certain advantages as a trading centre, which have helped it to grow The very fact that it is the capital has helped it to grow.

Mr. Gupta said that the development of Delhi has suffered. I would like to ask hon. members from other parts of the country whether they agree that Delhi has developed less than the urban or rural centres in their parts of the country, If any one of them says that Delhi is less developed, I will accept Shri Kanwar Lal Gupta's verdict. Whether you go by the evidence of your eyes or by Plan allocations whatever way you go into this fact, Delhi has developed and is developing particularly because the allocations made by the Centre are sufficient.

Taking all these factors into consideration, I think, it would not be in the national interest to consider an administrative arrangement which involves grant of statehood to Delhi. I think, this satisfies my hon. friend.

There was some mention of having a Legislative Assembly and a Council of Ministers. This experiment had also been tried between 1952 and 1956 and was then given up.

He made a point that Pandit Nehru gave an Assembly to Delhi and, therefore, there was some sanctity behind it. May I remind him that Pandit Nehru also took away the Assembly in 1956 ?

I entirely agree with my hon. friend, Shastriji, who talked of the necessity for developing the civic amenities of Delhi and of taking into account all the needs of

Delhi as a vast and developing urban complex-problems like slum clearance, reconstruction and redevelopment, city planning, transport, education, water, sewage and so on. They are going to be the major issues which the capital will face; in fact, even tody it is facing many of these issues and the Central Government is associating itself directly in solving many of these problems not only by providing the necessary resources but also by providing the necessary technical expertise.

It is in this context that we are examining the recommendations of the Administrative Reforms Commission which has made various important recommendations. I do not think I should take the time of the House by going into the details of those recommendations.

श्री कंवरलाल गुप्त : ए.आर.सी. की सिफारिशों के बारे में आपने राज्य सभा में कहा था कि कारपोरेशन तोड़ी जा सकती है इलैक्शन के बाद भी। मैंने यह कहा है कि आप पहले फैसला करे कि कारपोरेशन रहेगी या नहीं रहेगी। इलैक्शनस में अगर जन जीत गया तब तोड़ दी जाए और अगर कांग्रेस जीत गई तो न तोड़ी जाए, यह बात नही होनी चाहिये। इसका पहले फैसला हो जाना चाहिये।

मैंने यह भी कहा था कि आगे ढांचा क्या होगा, क्या सरकार ने इस पर सोचा है। इसके बारे में भी कुछ बता दीजिये।

SHRI K. C. PANT : One small victory in Delhi has gone to his head. He reads so much in this little victory in Delhi that he thinks that the Central Government is motivated by political considerations in these matters. I can only feel a little sorry for him. Delhi obsesses him so much. It is his constituency, but he is a man who, I thought, looked at these things from a larger point of view and not only from the point of view of Delhi, politics and elections. These are not the issues that can determine the future of Delhi. That has to be determined on its own merits and on greater considerations.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You have been indulging in these things.

SHRI K. C. PANT : He asks, what are our ideas ? I said, we are considering the ARC's recommendations. I had discussions with some of the authorities in Delhi-the Lieutenant-Governor, the Mayor and the Chief Executive Councillor. I propose to have further discussions.

The other question he asked was about my Rajya Sabha speech. I will come to that presently, but all I can tell him is that at this particular stage we have not come to any decision. I do not know why he has a feeling that in the Rajya Sabha I said that the Corporation would be dissolved.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : May be dissolved.

SHRI K. C. PANT : I have got it here and if I may be permitted I will like to quote from the question and answer in Rajya Sabha on the 12th November to which he is referring. I said that the question of election to the Corporation was not really connected with the future set-up of Delhi, because if we held up the elections then too we could be accused of holding up the elections unnecessarily. The Jana Sangh is in power. They may come back in power. Why should we hold them up ?

Now, it seems you are not confident of coming back to power. It seems you are hesitating to go into the fray. Why this hesitation ? It will create a bad impression in Delhi if it is known that you are hesitating to go in for elections.

श्री कंवर लाल गुप्त : हम तो कभी भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, आप आऐं तो सही। मेरा कहना यह है कि पहले कर लें। यह न हो कि आप हार जाएं उसके बाद आप करें। इसका जवाब आपके पास कुछ है ?

SHRI K. C. PANT : The two issues are unconnected. The elections to the Municipal Corporation will be held as scheduled in the month of March. It has nothing to do with this. Even if, ultimately, we take a decision on the recommendation of the ARC whatever decision we take, we will have to bring forward a legislation. It will take a certain length of time. It is not going to happen tomorrow. Should we hold up the normal process of having the elections to the Municipal Corporation because we have not come to a decision yet, I do not think that will be proper. Therefore, in the interest of doing normal things at the normal time, we are holding the elections. I do not want to confuse it with the larger issue of the future set-up of Delhi.

18.37 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 27, 1970/ Agrahayana 6, 1892 (Saka).

Diamond Printing Press Jaipur–3